Deposits of Minerals in Gujarat

4207. SHRI VEKARIA Will the Minister of STEEI AND MINFS be pleased to state·

(a) whether Government propose to conduct extensive survey by Geological Survey of India in Gujarat in view of the availability of large deposits of various minerals there, and

(b) if so, the main features thereof and the time by which it would be done ?

THE MINISTER OI STATF IN THE MINISTRY OF STELL AND MINES (SHRI SHAHNAWAZ KHAN) (a) and (b) Geological and mineral surveys by the Geological Survey of India in Gujarat are already in progress since several decades Gener il geological survey of the State is almost complete Geological mapping on modern maps and detailed mineral investigations are also in progress as per ten year plan (1969-79) of Geological Survey of India First phase (1969-74) of ten year plan, include systematic mapping and preliminary assessment in about 8500 sq km and regional mineral assessment including about 23,000 metres drilling and pitting, trenching, sampling for base-metals, phosphate fluorspar, china-clay, bentonite and bauxite besides groundwater investigations Certain areas of the State are also proposed to be covered by aerial geophysical surveys under B. R. G M Contract Current held season programme includes investigations for polymetallic mineralization in Banaskantha Sirohi belt bauxite in Jamnagar, Junagarh, Amreli and Bhavanagar districts, nickel in Sabarkantha district, tin in Banaskantha and Sabarkantha districts and fluorspar in Broach district

महेन्द्र राजपथ परियोजना के बारे में भारत नेपाल समझौता

4208. श्री डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) हाल ही में भारत और नेपाल के मध्य महेन्द्र राजपथ के बारे में सम्पन्न समझौते का ब्यौरा क्या है , और

(ख) इस परियोजना पर भारत सरकार कितना व्यय करेगी ?

विदेश मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) (क) और (ख). हाल में महेन्द्र राजपथ के संबंध में भारत और नेपाल के बीच कोई करार सम्पन्न नहीं हुआ है।

लेकिन, पहले के एक करार के अनुसरण में, जिसपर भारत और नेपाल ने 1966 में हस्ताक्षर किए, महेन्द्र राजपथ का एक भाग, झापा से जनकपुर (पूर्वी क्षेत्र) तक, 22 करोड़ रू० की लागत पर निर्मित हो चुका है।

इस्पात का आयात

4209. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय
श्री राम सहाय पाण्डे .

क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) 1970-71 की तुलना में 1971-72 में इस्पात का आयात कितने प्रतिशत बढ़ा है; और

(ख) इस्पात का आयात कम करने और देश में स्थित, इस्पात कारखानों को निर्धारित क्षमता अनुसार चलाने तथा उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क). 1971-72 (अप्रैल - सितम्बर 1971) में 5.05 लाख टन इस्पात का आयात किया गया

जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि मे 2.30 लाख टन का आयात किया गया था। इस प्रकार इसमे 120 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

(ख) वर्ष 1972-73 के लिए सरकार ने 72 लाख टन इस्पात पिण्ड का उत्पादन-लक्ष्य रखा है जो कि सर्वतोमुखी इस्पात कारखानो की क्षमता का लगभग 4 5 है। अगर उत्पादन निर्धारित लक्ष्य के अनुसार होता है तो 1972-73 मे इस्पात के आयात मे कमी हो जायेगी । 72 लाख टन इस्पात पिण्ड का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हर सभव उपाय किये जा रहे है। उस उदेश्य से हिन्दुस्तान स्टील लि० के कारखानो के कार्यकरण की समीक्षा सबधी मत्री द्वारा कायकरण समीक्षा बैठक मे हर तीसरे महीने की जाती है । इसके अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र के हरेक कारखाने के लिए एक टास्क फोस है जिसकी बैठक लगभग हर दो महीने मे एक बार होती है । यह हरेक कारखाने के उत्पादन की समीक्षा करती है, उसकी समस्याओ पर विचार-विमर्श करती है तथा उनके समाधान के लिए किय गय उपायो पर अनुवर्ती कारवाई करती है ।

सरकार टिस्को तथा इस्को की समस्याओ को जानने के लिए उनसे सतत सम्पर्क बनाए रखती है तथा उनके उत्पादन मे वृद्धि के लिए हर सभव सहायता देती है ।

इस्पात कारखानों का विस्तार

बोकारो इस्पात कारखाने का, जिसके प्रथम चरण की वार्षिक क्षमता 17 लाख टन की है और जिसे 1973-74 मे चालू करना है, द्वितीय चरण मे 40 लाख टन तक विस्तार किया जा रहा है। तृतीय चरण मे बोकारो इस्पात कारखाने की वार्षिक क्षमता को 55 लाख टन तक बढाने की शक्यता की जाच की जा रही है ।

भिलाई इस्पात कारखाने की क्षमता को भी 25 लाख टन इस्पात पिण्ड की वार्षिक क्षमता से बढाकर उगभग 40 लाख टन तक करने का विचार है ।

इस्को को अपनी 10 लाख टन इस्पात पिण्ड की वार्षिक क्षमता को बढ़ाकर 13 लाख टन तक करने की अनुमति दे दी गई है ।

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के अन्य सर्वतोमुखी इस्पात कारखानो की क्षमता के विस्तार की शक्यता पर भी विचार किया जा रहा है ।

National Council of Trade Union Centres

4210 SHRI P M MEHTA Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether the I N T U. C Working Committee has decided to work for the formation of National Council of Trade Union Centres— I N T U. C, A I T U. C and H. M. S ,

(b) if so, the main features of the proposal, and

(c) whether Government have approved the proposal ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI R K. KHADILKAR) : (a) Yes, Sir

(b) The details about the formation of the Council have to be worked out by the three participating Trade Union Centres